and pensions, especially in the Department of Pensions and Pensioners' Welfare;

(b) whether any such letter relates to non-payment of dues that can be paid to the widow of a government servant who dies in harness;

(c) whether any instructions have been issued to pay dues in such cases to the widow; and

(d) if not, by when the relevant instructions/clarifications would be issued?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI R. JANARTHANAM): (a) 121 (One hundred and twenty one) letters were received from the Members of Parliament during the period from 1.4.97 to 30.4.98 of which 42 letters are pending as on 30.4.98.

(b) No Sir. However 7 (seven) letters relate to payment of family pension to the widows of employees of Public Sector Undertakings and autonomous bodies have been received and referred to the concerned Ministries for necessary action.

(c) and (d) The matter has been taken up with the concerned Ministry and it is for the concerned Ministry to take necessary action as per the existing rules.

Rules regarding dismissal from service and withholding retirement benefits

219. SHRI RAJ NATH SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether dismissal from service and withholding of retirement benefits for unauthorised absence from duty constitute two punishments fro one wrong in the light of the Supreme Couurt's ruling in Mahanga Singh case of 1992;

(b) if so, the rules in this regard; and

(c) the remedies available to the aggrieved person?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI R. JANARTHANAM): (a) No, Sir.

(b) and (c) Dismissal from service is a penalty prescribed under the disciplinary rules. Withholding retirement benefits on dismissal is merely a consequential result thereof as the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 provide that dismissal or removal of a Government servant from a service or post entails forfeiture of his past service.

Raising of retirement age of Central Government Employees

220. DR. ALLADI P. RAJKUMAR: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government are considering raising retirement age of Central government employees to 60 years from 58 years at present;

(b) if so, the detailed reasons for the proposed change and the present status of the deliberations;

(c) whether State Governments have been consulted on the issue; and

(d) if so, the reaction of the State Governments in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI R. JANARTHANAM): (a) and (b) The age of retirement for civilian Central Government employees has been raised by two years excap for those already retiring at 60 years. Similarly, the age of retirement in the Armed Forces and the Central Para Military Forces is also being raised by two years.

(c) and (d) The age of retirement for State Government employees is the concern of the respective State Governments. Each State Government has to

take its own decision. In regard to raising of retirement age of Central Government employees there is no need to consult the State Governments. In regard to the All India Services, however, the State Governments were consulted and their views were taken into consideration.

प्रशासनिक सुधारों के लिये प्रस्ताव

221. **श्री ओंकार सिंह लखावत:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जन शिकायतों के निवारण और त्वरित और समयबद्ध कार्य निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिये प्रशासनिक सुधार करने की सरकार की मंशा है; और

(ख) क्या सरकार के पास प्रशासन की "परिणामोन्मुख" उत्तरदेयता को सुनिश्चित करने और प्रशासनिक स्थापना व्यय कम करने के लिये कोई प्रस्ताव है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त (बैंकिंग, राजस्व और बीमा) मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० जनार्दनम): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय में एक वरिष्ठ अधिकारी के अधीन एक विकेन्द्रीकृत आंतरिक लोक-शिकायत-निवारण-तंत्र स्थापित किया गया है। प्रशासनिक सुधार तथा लोक-शिकायत विभाग एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है तथा इस शिकायत-निवारण-तंत्र के कार्यकरण की आवधिक रूप से समीक्षा करता है।

प्रभावी, उत्तरदायी और संवेदनशील प्रशासन तथा नागरिकों के प्रति अनुकूल और सहानुभूतिपरक सरकार सुनिश्चित करने के बारे में सरकार के निर्णय के एक हिस्से के रूप में, उपर्युक्त विभाग ने:

(i) महत्वपूर्ण सरकारी-भवनों में सूचना-सुविधा काउंटर स्थापित किए हैं;

(ii) लोगों को सेवाएं प्रदान करने में लगी एजेंसियों में जवाबदेही तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के प्रयोजन से लोक-सेवाओं के प्रति नागरिकों की अनिवार्य हक़दारी समाविष्ट करते हुए, नागरिक-चार्टर बनाने के क्रम में विशेष पहल की है;

(iii) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों से शिकायतों की पावती भेजने एवं उन्हें अंतिम रूप से निबटाने हेतु समय-सीमा निर्धारित करने के लिए कहा गया;

(iv) मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों को इस आशय के दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि यदि कोई शिकायत-याचिका नामंजूर कर दी जाए तो ऐसी नामंजूरी के कारण सूचित किए जाने चाहिए।

संवेदनशील प्रशासन सुनिश्चित किए जाने के क्रम में लागू किए गए बीस-सूत्री कार्यक्रम, 1986 के बीसवें सूत्र के रूप में और एक मूल तत्व-स्वरूप, प्रशासन में जवाबदेही लागू की है।

केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के कार्यालयों में लागू कार्यालय-पद्धति के मेनुअल की प्रक्रियाओं के सरलीकरण के बारे में जब कभी निर्णय लिया जाता है, तो उपर्युक्त विभाग द्वारा उन्हें सरलीकृत किए जाने के कदम उठाकर शीघ्र निबटारा सुनिश्चित करने के सतत प्रयास किए जाते हैं। उपर्युक्त विभाग ने प्रशासनिक व्यय कम करने के बहुत से उपाय शुरू किए हैं, जैसे कि सभी मंत्रालयों/विभागों के कर्मचारियों में 10 प्रतिशत कर्मचारियों की कटौती, नए पदों के सृजन पर प्रतिबंध, टेलीफोनों/मोबाइल फोनों/पेजरों के उपयोग पर प्रतिबंध, नए वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध, समयोपरि भत्ते, पेट्रोल, विभिन्न बैठकों/सम्मेलनों/संगोष्ठियों के दौरान अतिथि-सत्कार, मंत्रियों के कार्यालय तथा उनके आवास के कार्यालय-संबंधी भाग की साज-सज्जा संबंधी व्यय पर प्रतिबंध। सामान्य वित्तीय नियम, 1963 में भी ये अनुदेश निहित हैं कि प्रशासनिक प्राधिकारी, अन्य बातों के साथ-साथ सार्वजनिक प्रयोजनों से, धन खर्च करते समय किफायत बरते जाने की आवश्यकता ध्यान में रखें।

Injustice done to Pensioners

222. SHRI PARAG CHALIHA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the injustice done to pensioners who retired prior to 1.1.86 and 1.1.96 as a result of implementation of recommendations of the Fifth Central Pay Commission;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the steps teken/contemplated to extend justice to them?